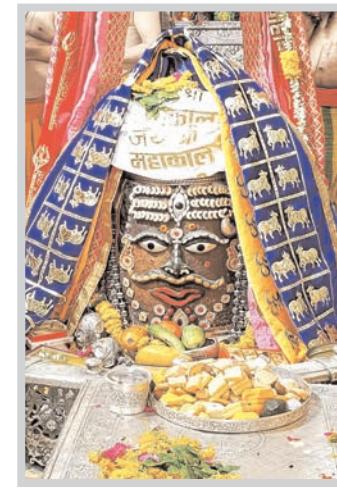


# मिटी चैफ

सम्पूर्ण भारत में चर्चित हिन्दी अखबार



इंदौर, गुरुवार, 04 जून 2024

## भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम समेत 8 ठिकानों पर पुलिस की दबिश

हाथरस सत्संग में मची भगदड़ में अब तक 123 की मौत

उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस सत्संग में हुए भीषण हादसे को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। बुधवार देर रात से पुलिस की टीम भोले बाबा और उनके सेवादारों की तलाश में छापेमारी कर रही है। फिलहाल, सत्संगी भोले बाबा कहां हैं, इसकी कोई पुस्तका जानकारी नहीं मिली है। गुरुवार सुबह तक पुलिस ने बाबा के मैनपुरी जिले में स्थित राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट (आश्रम), कानपुर, हाथरस समेत ग्वालियर 8 ठिकानों पर दबिश डाली। हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ और अच्युतस्थाओं के चलत अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 13 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद बुधवार रात भोले बाबा का पहला बयान आया है। हालांकि, बाबा सामने नहीं आया। उसने सुप्रीम कोर्ट के बकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया। जिसमें भोले बाबा से कहा कि मैं पहले ही सत्संग स्थल से चला गया था। जिसके बाद वहां जूनूद कुछ अराजक तत्वों ने दगभड़ मचाई। उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। इस हादसे के पीछे भोले बाबा ने आयोजकों को जिम्मेदार बताया है। साथ ही धायलों के स्वरूप

### हाथरस हादसे के किसी दोषी को नहीं बरखेंगे: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के जिला अस्पताल में भर्ती धायलों और पीड़ितों का हाल जानने के बाद प्रेस कॉफेंस की। उन्होंने कहा- सत्संग के प्रवचनकर्ता जब निकल रहे थे, तब त्रद्धातुओं की भीड़ उन्हें छोड़ दी गई थी। इसी दौरान हादसा हुआ। यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी हाथरस में कैंप किए हुए हैं। ये हादसा है या साजिश इसकी पूरी तह तक जाएंगे।



सीएम योगी ने बताया कि हाथरस हादसे की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की जा रही है। भगदड़ को घटाना की न्यायिक जांच भी की जाएगी। हाइडरेट के रिटायर्ड जज की देखरेख में एसआईटी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करेगी। साथ ही ऐसे आयोजनों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की जा रही है।

मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक, यूपी पुलिस ने सत्संग के आयोजक और मुख्य सेवादार

देवप्रकाश मधुकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, इसमें बाबा का नाम नहीं है। उधर, भोले बाबा के मैनपुरी में छिपे होने की जानकारी आ रही है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। दूसरी ओर, आरोप है कि आयोजकों ने भगदड़ में मारे गए लोगों के सामान खेतों में छिपा ए गए,

ताकि हादसे की भयावहता पर पर्दा ढाला जा सके। भोले बाबा एटा जिले की पट्टयाली तहसील के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन में एसआईटी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करेगी। उसका असली नाम नारायण साकार हरि है। एक प्रवचन में बताया था कि वह गुप्तचर ब्यूरो में पदथ्य थे। बाबा के ज्यादातर अन्यायी परिचम यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखण्ड में हैं।

### टीम इंडिया से पीएम मोदी की मुलाकात



टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया गुरुवार सुबह भारत लौट आई। रोहित शर्मा एंड कंपनी के साथ ही टीम के सोपोर्ट स्टाफ और कुछ मीडियाकर्मियों को लेकर आई एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट ने सुबह 6.15 बजे नई दिल्ली में लौंड किया। इसके बाद एक कर खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकले और बस में सवार हुए। टीम यहां से आईटीमी मीरा होटल गई। पूरे राते फैन्स का हुजूम रहा। क्रिकेट प्रेमी वर्ल्ड चैम्पियन्स का दीदार करने और स्वागत करने के लिए बेताब नजर आए।

#### पीएम मोदी से मुलाकात

खिलाड़ी कुछ दूर होटल में स्कैप। यहां से पीएम आवास के लिए रवाना होने से पहले खिलाड़ियों ने स्पेशल किक किया। यह केस के बाद इंडिया की जीती की खुशी में बाचाया गया था। विराट कोहली भी कैंप काटते नजर आए। यहां से खिलाड़ी के स्पेशल बस में सवार होकर पीएम आवास के लिए रवाना हुए। अभी पीएम मोदी के साथ मुलाकात जारी है बीसीसीआई के उपायक्षम राजीव शुक्ला के अनुसार, भारतीय टीम सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके घर पर मुलाकात करेगी। इसके बाद टीम मुंबई रवाना होगी। मुंबई में बैनर्डेंड स्टोरियों में टीम का स्वागत होगा। यहां से खिलाड़ी खुली बस में बाहर होकर नरेंद्र मोदी के लिए आएंगे। यहां भी खिलाड़ियों का स्वागत और समान होगा। बीसीसीआई ने विराट विजेता खिलाड़ियों को 125 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है। इसी समान समारोह में खिलाड़ियों को यह राशि प्रदान की जाएगी।

**मप्र का 2024-25 का बजट:** कांग्रेस के हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया, नए टैक्स नहीं होने से जनता को राहत, पेट्रोल-डीजल पर कोई राहत नहीं

## मप्र की मोहन सरकार का पहला बजट...

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को पेश किया। मप्र के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कथित नस्तंग कॉलेज घटाले के मुद्दे को लेकर विपक्ष कांग्रेस के हंगामे के बीच 2024-25 के लिए बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने 3.75 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश किया है। सरकार के पहले पूर्ण बजट में आम लोगों को रात देते हुए उनके पर किसी भी प्रकार का कार्ड टैक्स का बोझ नहीं लगाया गया है।

सरकार की ओर से महिलाओं, किसानों, युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा सेक्टर में विशेषताएँ से फोकस किया गया है। इसी के साथ ही ऊर्जा सेक्टर पर भी मोहन यादव सरकार की प्राथमिकता रहेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बजट में महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही खेती के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर भी जीर्ण दिया गया है। इसके अलावा, बजट में यादव सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के साथ ही व्यारोजगार से जोड़े पर भी फोकस किया है। देवड़ा ने 2024-25 के बजट में जो प्रमुख घोषणाएँ की हैं, उनमें पीएम ई-बस योजनांतर्गत छह शहरों (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं सागर) में भारत सरकार की सहायता से 552 ई-बसों का संचालन करना शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने पांच साल में वार्षिक बजट के आकार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। 2024-25 के लिए 3,65,067 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है, जो 2023-24 के 3,14,025 करोड़ रुपये के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है।



#### बजट की खास बातें

- 3800 करोड़ की धनराशि केंद्र से अतिरिक्त मिलेगी, जिसे विकास की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
- 22 नए ई-ऑफिस योजना की तैयारी है मध्यप्रदेश के कई जिलों में।
- 46000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी भर्ती।
- 22 हजार 600 करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा के लिए।
- 21 हजार 144 करोड़ रुपये लोगों की सेहत के सुधार के लिए।
- 4 हजार 725 करोड़ रुपये वन और पर्यावरण के लिए।
- 11000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं।
- 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे।
- 87 लाख विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तक और गणेश दिए जाएंगे।

#### किस क्षेत्र में कितना बढ़ा बजट

- कृषि क्षेत्र का बजट 15 प्रतिशत बढ़ा। स्वास्थ्य के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 56 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी।

- शिक्षा के बजट में वार प्रतिशत, एसटी, एसटी और ओवीसी वर्गों की योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत, इफास्टरक्चर क्षेत्र में 9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

- नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए 13 प्रतिशत, संस्कृति संवर्धन के लिए 35 प्रतिशत, रोजगार के लिए 39 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

#### 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ेगा

अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृहों में 660-660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण होगा। 603 सर्किंट किमी पारेष्यन लाइनों पर 2,908 मेगावाट क्षमता के अति उच्च दाव उपकरण के कार्य प्रस्तावित हैं।

#### प्रति व्यक्ति आय हुई 1.42 लाख रुपए

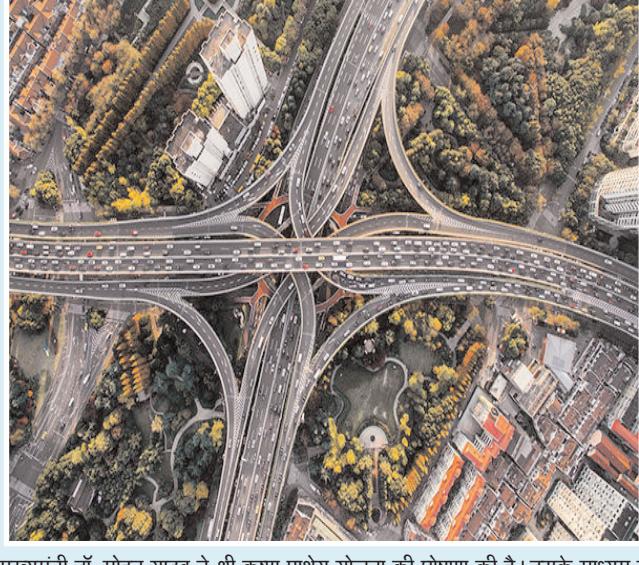






# 2024-25 के लिए 3,65,067 करोड़ रुपए के त्यय का प्रावधान, जो 2023-24 के 3,14,025 करोड़ रुपए के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक

## इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार की खास योजनाएं



**उज्जैन जाने वाला हर मार्ग चार या आठ लेन बनेगा**  
मध्यप्रदेश में अगले पांच साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नमंदा प्रगति पथ, 676 किमी के विष्य एक्सप्रेस-वे, 450 किमी का मालवा-निमाड विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखण्ड विकास पथ एवं 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ बनाया जाएगा। इनके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं गोपालगढ़ में एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं। सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में बायपास के साथ शहर में आगे वाले सभी मार्गों को चार लेन अथवा आठ लेन किया जाएगा।

### रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा

राज्य सरकार ने संस्कृत विभाग के लिए 1,018 करोड़ रुपए रखे हैं। यह 2023-24 के मुकाबले 250 प्रतिशत अधिक है। इस राशि से भारत के कालजयी महानायकों की तज़िरत का संग्रहालय वीरी भारत रायस स्थापित किया जा रहा है। यह देश और दुनिया का अपनी तरह का पहला संग्रहालय होगा। भगवान श्री राम ने वनवास के द्वारा राम प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पथ गमन किया। राज्य की सीमाओं के अंतर्गत राम पथ गमन के अंतर्गत वारे सभी मार्गों को चार लेन अथवा आठ लेन किया जाएगा।

### मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री कृष्ण पाथथय योजना की घोषणा की है। इसके माध्यम से प्रदेश में श्री कृष्ण पथ के पुनरावेषण और संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है।

### पांच साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का जाल

अगले पांच साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नमंदा प्रगति पथ, 676 किमी के विष्य एक्सप्रेस-वे, 450 किमी का मालवा-निमाड विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखण्ड विकास पथ एवं 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ बनाया जाएगा। इनके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं गोपालगढ़ में एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं। सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में बायपास के साथ शहर में आगे वाले सभी मार्गों को चार लेन अथवा आठ लेन किया जाएगा।

### पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना

2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना निर्माण की सैद्धांतिक सहायता बनाई गई है। इससे प्रदेश के 10 ज़िलों में चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और पेंजल मिलता सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केन बेतावा लिंक परियोजना और केन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

### नगरीय विकास के लिए 16744 करोड़

नगरीय क्षेत्रों में जन भागीदारी के माध्यम से दो संरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन यापन के लिए नगर वीरीकरण योजना लागू की जाएगी।

### प्रदेश के 6 शहरों में चलेंगी 552 ई-बसें

शहरों के मास्टर प्लान की सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कायाकल्प योजना के लिए नगरीय क्षेत्र में आदर्श संरचना निर्माण योजना के लिए 1100 करोड़, मुख्यमंत्री अधीन संरचना विकास योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की बस योजना अंतर्गत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, गोपालगढ़, उज्जैन और सागर में 552 बसों का संचालन किया जाएगा।

### भोपाल और इंदौर में जल्द शुरू होगी मेट्रो

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सभी निकायों को समिलित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं जल प्रबंधन के लिए आगामी 5 वर्ष में 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

## बजट में शिक्षा के लिए ये प्रावधान....



सीएम राइस स्कूलों में परिवहन व्यवस्था: वर्ष 2024-25 में 150 सीएम

राइस स्कूल नवीन भवन में संचालित होंगे।

इन विद्यालयों में एक किलोमीटर से अधिक

पर नियन्त्रित की कार्यवाही की जा रही है।

730 स्कूलों को पीएम श्री योजना अंतर्गत चिह्नित किया है। शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के

साथ भौतिक संसाधनों का उन्नयन भी किया जाएगा।

प्रदेश के बैगा, भारिया, सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु

पीएम जन-मन योजना के अंतर्गत इस वर्ष

22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे।

लागू की गई है। सीएम राइस विद्यालयों के

लिए 2737 करोड़ रुपए का प्रावधान किया

है।

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस : उच्च

शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार और बुनियादी

दांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पीएम उमा परियोजना के तहत प्रदेश में 565 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है।

प्रत्येक ज़िले में एक कॉलेज की प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। इन कॉलेजों के लिए उज्जैन में चना तथा गोपालगढ़ में निशुल्क खाद्यात्र उपलब्ध कराया जा रहा है। जो आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री उज्जैन योजना में शामिल होने से वित्त हितग्राहियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

**पशुओं को घर पहुंच विकित्सा**

मई 2023 से प्रारंभ 406 चालित पशु विकित्सा इकाइयों ने अब तक 5.46 लाख से अधिक पशुओं को घर पर चिकित्सा सुविधा दी है। चालित पशु विकित्सा इकाइयों में 82 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सहकारी दुष्प्राप्त उत्पादक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत दुष्प्राप्त उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से प्रति लैटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट।

**गौ-वंश रक्षा वर्ष मनाएंगे**

2,190 गौ-शालाओं का संचालन हो रहा है। इनमें लगभग तीन लाख गौ-वंश का पालन हो रहा है। प्रति गौ-वंश प्रति दिन 20 रुपये दिए जाते थे, जिसे दोगुना कर 40 रुपए किया जाएगा। तीन गुना वृद्धि करते हुए बजट में 250 करोड़ रुपये रखे रहे हैं। 2024-25 को गौ-वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

## विपक्ष का हंगामा, विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग

बजट पेश करने के लिए जैसे ही सदन की कार्रवाई बुधवार को शुरू हुई, विपक्ष के नेता उमंग सिंहारां और अन्य कांग्रेस सदस्यों ने कथित घोटाले के सिलसिले में मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की। बजट भाषण शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष को यह मुद्दा उठाने के लिए मंगलवार को

पर्याप्त समय दिया गया था और उन्हें बजट पेश किए जाने के दौरान सदन की परंपरा के अनुसार इसमें भाग लेना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयरायगिरि ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधानसभा की कार्यवाही सदन के नियमों और परंपराओं के अनुसार चलेगी और विपक्ष को उचित प्रक्रिया के

तहत अपनी शिकायतें उठानी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि सदन के नियमों में ढील दिए जाने के बाद विपक्ष मंगलवार को यह मुद्दा उठा चुका है। विपक्षी सदस्यों ने विजयरायगिरि की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे आसन के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते रहे और फिर वहीं बैठ गए।

## महिलाओं के लिए सरकार के प्रयास जारी...

महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह गत वर्ष से 81 अधिक है महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीन विकास के लिए सभी विभागों में योजनाएं संचालित हैं। जैंडर बजट 2024-25 का 1,21,997 करोड़ रुपये है। लाडली बन्धी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर संरचना गया। लाडली लक्षी योजन





